पंजाब नेशनल बैंक

बनाम

आर.एल. वैद और अन्य

20 अगस्त 2004

[अरिजीत पसायत और सी.के. ठक्कर, न्यायमूर्ति]

मिसाल :

कुछ दस्तावेजों को तलब करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपी द्वारा आवेदन- सी.बी.आई. और बैंक का तर्क है कि दस्तावेज़ विशेषाधिकार प्राप्त संचार थे- विचारण न्यायालय ने आवेदन की अनुमति दी- उच्च न्यायालय ने केवल एक निर्णय का हवाला देकर बैंक की याचिका को खारिज कर दिया- माना, केवल निर्णय पर भरोसा रखकर मामलों का निपटान किया जाता है उचित नहीं है- उच्च न्यायालय को कारण बताना चाहिए था और तत्काल मामले के तथ्यों पर निर्णय की प्रयोज्यता के बारे में भी बताना चाहिए था- धारा 124, साक्ष्य अधिनियम, 1872

उत्तरदाताओं, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1) (डी) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे थे, ने कुछ दस्तावेजों को तलब करने

के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया। सीबीआई और अपीलकर्ता बैंक ने यह कहते हुए प्रार्थना का विरोध किया कि दस्तावेज़ साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 124 के संदर्भ में विशेषाधिकार प्राप्त संचार थे। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन की अनुमति दी। बैंक ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसने कहा कि आर.के. जैन मामले के फैसले के आलोक में, बैंक का कोई मामला नहीं बनता।

बैंक द्वारा दायर अपील में यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय को तत्काल मामले के तथ्यों पर आर के जैन के फैसले की प्रयोज्यता पर चर्चा किए बिना, बैंक के आवेदन को खारिज नहीं करना चाहिए था।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए कहा :

1. केवल किसी निर्णय पर भरोसा रखकर मामलों का निपटारा करना उचित नहीं है। यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक कथन किसी विशेष मामले के तथ्यों की सेटिंग में किए जाते हैं। परिस्थितिजन्य लचीलापन, एक अतिरिक्त या भिन्न तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर ला सकता है। उच्च न्यायालय ने निर्णय में केवल आरके जैन मामले का उल्लेख किया है, बिना यह बताए कि उक्त निर्णय की प्रयोज्यता और मामले के तथ्यों के साथ इसकी कोई प्रासंगिकता कैसे है। उच्च न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह कारण बताए और मामले के तथ्यों पर

निर्णय की प्रयोज्यता के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताए। [695-ए-सी]

आर.के. जैन बनाम भारत संघ, एआईआर (1993) एससी 1769, संदर्भित।

2. उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को कानून के अनुसार नए विचार के लिए उसके पास भेजा जाता है। किशन नारायण के मामले में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण** पर भी विचार किया जाएगा क्योंकि यह विशेषाधिकार के प्रश्न से विस्तृत रूप से संबंधित है। उक्त मामले में व्यक्त दृष्टिकोण की तात्कालिक मामले के तथ्यों पर लागू होने से निपटना उचित होगा। [695-डी-ई] **किशन नारायण बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1974] 3 एससीसी 368, संदर्भित।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 917/2004

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2003 के सी.आर. संख्या 1413 में निर्णय और आदेश दिनांक 11.7.2003 से। अपीलकर्ता की ओर से ध्रुव मेहता और मोहित चौधरी। उत्तरदाताओं के लिए प्रशांत कुमार के लिए गौरव अग्रवाल, पी परमेश्वरन के लिए विष्णु शर्मा।

कोर्ट का फैसला जस्टिस अरिजीत पसायत ने सुनाया।

अनुमति दी।

प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के कथित कमीशन के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 5(1)(डी) के साथ पढ़ें। मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में 'सीबीआई') द्वारा दर्ज किया गया था, जो वर्तमान अपील में प्रतिवादी नंबर 4 है। जैसा कि आवेदन में दर्शाया गया था, आरोपी व्यक्तियों द्वारा आठ दस्तावेजों को तलब करने के लिए सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने उसकी पेशी पर आपत्ति को खारिज करते हुए उसे पेश करने का निर्देश दिया। यह सीबीआई और अपीलकर्ता-बैंक का रुख था कि दस्तावेज़ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 124 के संदर्भ में विशेषाधिकार प्राप्त संचार थे। मूल रूप से, सीबीआई ने प्रार्थना का विरोध किया था और बाद में अपीलकर्ता-बैंक ने भी इसी तरह की आपत्तियां उठाईं। विशेष न्यायाधीश का विचार था कि पत्रों को प्रस्तुत करने से सार्वजनिक हित को कोई नुकसान नहीं होगा और इससे अदालत को उचित निर्णय पर पहुंचने में सुविधा होगी। यह नोट किया गया कि इस प्रकार की कार्यवाही में, अदालत को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता है, और न्याय प्रशासन में, अदालत को सभी प्रासंगिक सामग्रियों

तक पूरी संभव पहुंच होनी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 482 के साथ पठित धारा 401 के तहत संशोधन के लिए एक आवेदन दायर करके पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दी गई थी। आवेदन निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया गया:

> "यद्यपि ए.जी.एम., जो विभाग के प्रमुख थे, का हलफनामा दस्तावेजों के विशेषाधिकार का दावा करने के लिए दायर किया गया था, फिर भी, आर.के. जैन बनाम भारत संघ, [ए आई आर (1993) एससी 1769] में निर्णय के आलोक में, याचिकाकर्ता के पास कोई मामला नहीं है। इसलिए, खारिज किया जाता है।"

अपीलकर्ता के साथ-साथ सीबीआई का रुख यह है कि जब विशेषाधिकार का दावा किया गया था और वह भी ऐसे दस्तावेजों का जो गोपनीय प्रकृति के थे, तो विद्वान विशेष न्यायाधीश को उसे पेश करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था। किसी भी स्थिति में, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता-बैंक द्वारा दायर आवेदन को केवल यह कहते हुए खारिज करना उचित नहीं था कि आर. के. जैन बनाम भारत संघ (एआईआर (1993) एससी 1769) में निर्णय के मद्देनजर, अपीलकर्ता के पास कोई मामला नहीं है। मामले के तथ्यों पर उक्त निर्णय की प्रयोज्यता पर चर्चा नहीं की गई

है। दूसरी ओर, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 के विद्वान वकील ने कहा कि केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 का उल्लेख करते हुए, यह बताए बिना कि सार्वजनिक हित कैसे प्रभावित हुआ होगा, सीबीआई और अपीलकर्ता-बैंक को विशेषाधिकार का दावा करने का अधिकार नहीं है।

हमने पाया कि उच्च न्यायालय ने केवल आर के जैन के मामले (सुप्रा) का निर्णय में उल्लेख किया है, बिना यह बताए कि उक्त निर्णय की प्रयोज्यता और मामले के तथ्यों के साथ इसकी कोई प्रासंगिकता कैसे है। उच्च न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह कारण बताए और मामले के तथ्यों पर निर्णय की प्रयोज्यता के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताए। किसी निर्णय के शब्दों को ऐसे मानने में हमेशा जोखिम होता है जैसे कि वे किसी विधायी अधिनियम के शब्द हों और यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक कथन किसी विशेष मामले के विशेष तथ्यों में किए जाते हैं। परिस्थितिजन्य लचीलापन, एक अतिरिक्त या भिन्न तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर ला सकता है। केवल निर्णय पर भरोसा रखकर मामलों का निपटारा उचित नहीं है। मिसाल का पालन केवल तभी तक किया जाना चाहिए जब तक यह न्याय के मार्ग को चिह्नित करता है, लेकिन आपको मृत लकड़ी को काटना होगा और किनारे की शाखाओं को छांटना होगा अन्यथा आप खुद को झाड़ियों और शाखाओं में खोया हुआ पाएंगे, लॉर्ड डेनिंग ने इस मामले में बोलते हुए कहा। विवादित आदेश

निश्चित रूप से अस्पष्ट है।

इन परिस्थितियों में, मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर देते हैं और मामले को कानून के अनुसार नए विचार के लिए भेज देते हैं। इस न्यायालय द्वारा किशन नारायण बनाम महाराष्ट्र राज्य ([1974] 3 एससीसी 368) में व्यक्त दृष्टिकोण पर भी विचार किया जाएगा क्योंकि यह विशेषाधिकार के प्रश्न से विस्तृत रूप से संबंधित है। उक्त मामले में व्यक्त दृष्टिकोण की वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होने से निपटना उचित होगा। 2003 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1413, आपराधिक विविध मामला संख्या 29708/2003 के साथ पढ़ी गई, को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाए।

प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 के विद्वान वकील ने अर्ज़ किया कि उच्च न्यायालय द्वारा मामले के निपटारे तक विचरण, दस्तावेजों के तलबी की हद्द तक ही आगे बढ़ सकता है। विद्वान विशेष न्यायाधीश इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाने की वांछनीयता और व्यवहार्यता पर विचार करेंगे, खासकर जब सीबीआई और अपीलकर्ता-बैंक को रुख पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनीता यादव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।